

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4590

(दिनांक 20.08.2025 को उल्लंघन के लिए)

प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास

4590. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 'प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास' (बीआईएनडी) के अंतर्गत कोई परियोजनाएँ या योजनाएँ शुरू की गई हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो क्या बीआईएनडी योजना को 2022-26 के लिए 2,539.61 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी ताकि सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटलीकरण, हाई-डेफिनिशन स्टूडियो और एफएम विस्तार सहित दूरदर्शन और आकाशवाणी अवसंरचना का आधुनिकीकरण किया जा सके;
- (ग) क्या 2023-24 तक उपकरणों के उन्नयन, डिजिटल प्रसारण और 8 नए एफएम ट्रांसमीटरों पर 750 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने के साथ 900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं;

- (घ) क्या यह सच है कि मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, बीआईएनडी के अंतर्गत कोई भी बड़ी धनराशि व्यपगत नहीं हुई है और निविदा तथा अवसंरचना खरीद में देरी के कारण कभी-कभी संवितरण धीमा हुआ है, लेकिन सुव्यवस्थित खरीद और निगरानी प्रणालियों के माध्यम से इसका समाधान किया जा रहा है; और
- (ङ) क्या इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रसारण पहुँच में सुधार करना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) स्कीम देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रसारण अवसंरचना के विकास, आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। वर्ष 2021-26 के लिए बीआईएनडी स्कीम को 2539.61 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।

- यह एक अखिल भारतीय स्तर की पहल है जो सभी राज्यों को शामिल करती है।

- इसमें ट्रांसमीटरों और स्टूडियो का आधुनिकीकरण, डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म और डीडी टीवी चैनलों का विस्तार और प्रोडक्शन और ट्रान्समिशन सुविधाओं का उन्नयन शामिल है।
- यह सामग्री सृजन और नवाचार पर केंद्रित है और रणनीतिक, सीमावर्ती और वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोक प्रसारण की पहुँच का विस्तार करती है।

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही तक, बीआईएनडी स्कीम के अंतर्गत 980.69 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

डीडी फ्री डिश देश की एकमात्र फ्री-टू-एयर डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा है जो देश भर में बिना किसी सब्सक्रिप्शन लागत के विभिन्न टेलीविजन चैनल प्रदान करती है। डीडी फ्री डिश पर चैनलों की संख्या 2019 में 104 से बढ़कर वर्तमान में 510 हो गई है, जिसमें 92 प्राइवेट चैनल, 50 दूरदर्शन चैनल और 320 शैक्षिक चैनल शामिल हैं। इसके अलावा, 48 आकाशवाणी चैनल और एफएम गोल्ड, रेनबो और विविध भारती सेवा जैसे लोकप्रिय चैनल भी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में व्यापक व्यूअरशिप सहित भारतीय ऑडियंस को सेवा प्रदान करके, यह समाचार, सूचना, शैक्षिक कार्यक्रमों और प्राइवेट चैनलों तक व्यापक पहुँच में योगदान देता है।

आकाशवाणी का वर्तमान स्थलीय कवरेज भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से लगभग 90% और देश की जनसंख्या के हिसाब से लगभग 98% है। इसके अलावा, मोबाइल फोन पर भी "न्यूज़ऑनएआईआर" ऐप के माध्यम से 260 से अधिक आकाशवाणी चैनल सुने जा सकते हैं। इसके अलावा, लोक प्रसारण पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए **बीआईएनडी स्कीम** के तहत 59 नए एफएम ट्रांसमीटरों को अनुमोदित किया गया है।

प्रसार भारती ने वर्ष 2024 में अपना स्वयं का ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म "वेव्स" भी लॉन्च किया है, जो एक बहु-शैली डिजिटल स्ट्रीमिंग एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म है जो इन्फोटेनमेंट सामग्री प्रदान करता है। यह सूचना, शिक्षा और संस्कृति को सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के विभिन्न चैनल भी वेव्स में एकीकृत हैं।
